सत्यमेव जयते
पशुपालन और डेयरी विभाग
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
भारत सरकार

Ministry of Cooperation | सहकारिता मंत्रालय
Government of India | भारत सरकार

राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड

श्री नरेन्द्र मोदी
माननीय प्रधानमंत्री

श्री अमित शाह
माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री

श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह
माननीय मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी एवं पंचायती राज मंत्री

श्वेत क्रांति 2.0
White Revolution 2.0

श्वेत क्रांति 2.0

भूमिका

भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का मानना है कि "सहकार से समृद्धि" की परिकल्पना को साकार करने के लिए सहकारिताओं की शक्तियों का लाभ लेने और उन्हें सफल एवं जीवंत व्यवसायिक संस्थानों में रूपांतरित करने के सभी प्रयास किये जाने चाहिए क्योंकि देश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था, विशेषकर कृषि और संबंधित सेक्टरों में, विकास और समता के साथ आर्थिक परिवर्तन में सहकारिताओं की अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका है। यह सरकार की नीति है कि विभिन्न मंत्रालयों और विभागों की मौजूदा विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों के साथ सहकारिताओं के अभिसरण द्वारा सहकारी सेक्टर को सहयोग प्रदान किया जाए। देश के प्रथम सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह के कुशल नेतृत्व और मार्गदर्शन में सहकारिता मंत्रालय ने श्वेत क्रांति 2.0 लाने की पहल की है।

बहु उद्देशीय प्राथमिक कृषि सहकारी ऋण समितियों (MPACS) में डेरी की गतिविधियों की शुरूआत करने के लिए राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड (एनडीडीबी) के संसाधनों से 40,000/- रुपये प्रति MPACS के दर से 1,000 MPACS को वित्तीय सहायता प्रदान कर श्वेत क्रांति 2.0 का शुभारंभ किया जा रहा है। तदुपरांत, इस पहल को पशुपालन और डेयरी विभाग, भारत सरकार के प्रस्तावित राष्ट्रीय डेरी विकास कार्यक्रम 2.0 (NPDD 2.0) की वित्तीय सहायता से आगे बढ़ाया जाएगा। इस पहल से "सहकारिता आन्दोलन" और मजबूत बनकर उभरेगा।

श्वेत क्रांति 2.0

सहकारिता के माध्यम से संचालित "श्वेत क्रांति 2.0" का लक्ष्य सहकारी कवरेज में विस्तार, रोजगार सृजन और महिला सशक्तिकरण है और इसका उद्देश्य "अगले पाँच वर्षो में अनाच्छादित क्षेत्रों में दुग्ध उत्पादकों को बाजार की पहुंच उपलब्ध कराकर और संगठित क्षेत्र में डेरी सहकारिताओं की हिस्सेदारी को बढ़ाकर, डेरी सहकारिताओं द्वारा दूध संकलन को वर्तमान स्तर से 50% तक बढ़ाना है"।

परियोजना गतिविधियां

श्वेत क्रांति 2.0 के अंतर्गत परिकल्पित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए, सहकारी दूध संकलन में वर्तमान 6 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि के मुकाबले प्रतिवर्ष लगभग 9 प्रतिशत की वृद्धि करने की आवश्यकता है।

- प्रत्येक अनाच्छादित पंचायत में क्रियाशील डेरी सहकारी समितियों की स्थापना तथा वर्तमान पैक्स/डेरी सहकारी समितियों का सुदृढ़ीकरण किया जाएगा।
- इस पहल को राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड (NDDB) के सहयोग से पशुपालन और डेयरी की विभिन्न योजनाओं को "सम्पूर्ण सरकारी दृष्टिकोण" का लाभ उठाते हुए कार्यान्वित किया जाएगा।

पांचवें वर्ष के अंत तक, डेरी सहकारिताओं द्वारा दूध का संकलन बढ़कर 1000 लाख किलोग्राम प्रतिदिन होने की संभावना है। इसे दो महत्वपूर्ण गतिविधियों के माध्यम से हासिल किया जाएगा:

(i) डेरी सहकारिताओं के कवरेज में विस्तार
(ii) डेरी सहकारिताओं की पहुंच में वृद्धि

श्वेत क्रांति 2.0 के अंतर्गत वर्षवार प्रस्तावित लक्ष्य निम्नानुसार हैं -

मुख्य मापदंड	आधार वर्ष 2023-24	2024-25	2025-26	2026-27	2027-28	2028-29
सहकारी दूध संकलन (लाख किलोग्राम प्रति दिन)	660	720	780	847	923	1,007

चीज संयंत्र, साबर डेयरी, साबरकांठा, गुजरात

आविन डेयरी संयंत्र, शिवकाशी, तमिलनाडु

स्वचालित दूध संकलन इकाई

श्वेत क्रांति 2.0 के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए एक लाख डेरी सहकारी समितियों (DCS) की स्थापना/सुदृढ़ीकरण की योजना

इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, अगले पांच वर्षों के दौरान लगभग 56,000 नए बहुउद्देशीय डीसीएस (MDCS) स्थापित करने के लिए एनडीडीबी द्वारा एक कार्य योजना तैयार की गई है। नई ग्राम स्तरीय संस्थाओं (MDCS/MPACS) का निर्माण करने के बजाय यथा संभव, MPACS में दूध संकलन गतिविधियों की शुरूआत करके, अनाच्छादित क्षेत्रों में मौजूदा PACS का लाभ लेने के प्रयास किए जाएंगे।

इसके अलावा, यह परिकल्पना की गई है कि बेहतर और उन्नत दूध संकलन तथा परीक्षण के बुनियादी ढांचों जैसे स्वचालित दूध संकलन इकाई (AMCU), डेटा प्रोसेसर दूध संकलन इकाई (DPMCU), परीक्षण उपकरण, बल्क मिल्क कूलर आदि को आवश्यकतानुसार लगाकर लगभग 46,000 वर्तमान ग्राम स्तरीय DCS/PACS का सुदृढ़ीकरण किया जाएगा और वे MDCS/MPACS के रूप में कार्य करेंगे।

नये/सुदृढ़ किए जाने वाले डेरी सहकारी समितियाँ का राज्यवार ब्यौरा क्रमशः **अनुबंध-I** और **अनुबंध-II** में दिया गया है ।

प्रस्तावित राष्ट्रीय डेरी विकास कार्यक्रम 2.0 (NPDD 2.0)

श्वेत क्रांति 2.0 के लक्ष्यों को पशुपालन और डेयरी विभाग, MOFAH&D की नई प्रस्तावित केंद्रीय क्षेत्र की योजना, राष्ट्रीय डेरी विकास कार्यक्रम (NPDD) 2.0 के अंतर्गत शामिल कर लिया गया है।

इस योजना के अंतर्गत, निम्नलिखित घटकों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने की परिकल्पना की गई है:

क. ग्राम स्तर पर दूध संकलन प्रणाली की स्थापना

ख. गुणवत्तापूर्ण दूध संकलन के लिए मिल्क चिलिंग सुविधाएं

ग. प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण

प्रस्तावित NPDD 2.0 की EFC नोट परिचालित कर दी गई है और शीघ्र ही इसे मंजूरी मिलने की संभावना है। NPDD 2.0 का क्रियान्वयन पशुपालन और डेयरी विभाग द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाएगा।

परियोजना के लाभ :

- इससे छोटे डेरी किसानों को बाजार की पहुंच प्राप्त होने के साथ उचित एवं लाभकारी मूल्य सुनिश्चित होगा।
- इससे प्राथमिक डेरी सहकारिताओं के नेटवर्क को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी तथा दूध संकलन, परीक्षण, चिलिंग, लॉजिस्टिक और प्रसंस्करण अवसंरचना सहित संपूर्ण डेरी मूल्य शृंखला को मजबूती प्रदान करने में मदद मिलेगी।
- इससे महिलाओं की सदस्यता को अधिक बल मिलेगा जो डेरी क्षेत्र की महत्वपूर्ण हितधारक हैं।
- दूध संकलन में वृद्धि होने से डेरी उद्योग में संगठित क्षेत्र की हिस्सेदारी को बढ़ाने में मदद मिलेगी, जहाँ अभी भी असंगठित क्षेत्र का प्रभुत्व है। इससे खाद्य सुरक्षा एवं गुणवत्ता नियंत्रण सुनिश्चित करने और ताजा तथा स्वच्छ दूध एवं दूध उत्पादों की उपलब्धता बढ़ाने में मदद मिलेगी।
- इन पहलों से डेरी क्षेत्र के विकास और घरेलू मांग को पूरा करने के लिए दूध उत्पादन बढ़ाने के साथ-साथ निर्यात करने की क्षमता भी बढ़ेगी।

बनास डेयरी संयंत्र, बनासकांठा, गुजरात

गोकुल डेयरी संयंत्र, कोल्हापूर, महाराष्ट्र

वाराणसी डेयरी संयंत्र, वाराणसी, उत्तर प्रदेश

नंदिनी डेयरी संयंत्र, चनरायापटना, कर्नाटक

अनाच्छादित ग्राम पंचायतों में डीसीएस की स्थापना संबंधी एनडीडीबी की पायलट परियोजनाएं

एनडीडीबी ने जींद (हरियाणा), इंदौर (मध्य प्रदेश) और चिकमंगलूर (कर्नाटक) जिलों के अनाच्छादित पंचायतों के चिह्नित किए गए क्षेत्रों में डीसीएस स्थापित करने के लिए फरवरी 2023 में एक पायलट परियोजना की शुरूआत की जिससे जरूरी सहयोग का आकलन किया जा सके। पायलट परियोजना के तहत, 79 डीसीएस स्थापित किए गए हैं जो लगभग 2500 किसानों से 15 TLPD दूध का संकलन कर रहे हैं। परियोजना का कुल व्यय 3.8 करोड़ रुपये है।

दूध संकलन गतिविधियों की शुरूआत करने के लिए MPACS को सहयोग प्रदान करने संबंधी एनडीडीबी की योजना

श्वेत क्रांति 2.0 की परिकल्पना के अनुरूप, एनडीडीबी ने अपनी योजना के माध्यम से PACS/MPACS में दूध संकलन की गतिविधियों की शुरूआत करने के लिए PACS/MPACS को वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करने का निर्णय लिया है जिससे अतिरिक्त आय सृजन किया जा सके। इस योजना के अंतर्गत, 1000 MPACS को बुनियादी दूध संकलन और परीक्षण उपकरण खरीदने के लिए प्रति PACS/ MPACS को 40,000 रुपये का अनुदान दिया जाएगा। इस योजना को पूरे देश में डेरी सहकारी संस्थाओं के माध्यम से लागू किया जाएगा। इस योजना का कुल परिव्यय 4.00 करोड़ रुपये होगा, जिसे एनडीडीबी द्वारा वित्तपोषित किया जाएगा। इस योजना के तहत 1000 PACS/ MPACS को शामिल किया जाएगा और इस योजना का लाभ लेने के लिए विभिन्न राज्य एनडीडीबी को अपनी अभिरुचि की अभिव्यक्ति (expression of interest) प्रेषित कर रहे हैं। इस योजना से प्राप्त होने वाले लक्ष्य श्वेत क्रांति 2.0 में सन्निहित होंगे।

इस योजना के विवरण तथा दिशा-निर्देश **अनुबंध-III** में दिए गए हैं।

चूंकि उक्त योजना श्वेत क्रांति 2.0 का एक हिस्सा है, इसके शुभारंभ से हितधारकों के बीच इस योजना का व्यापक प्रचार -प्रसार होगा और साथ ही, इससे इस योजना के प्रचार प्रसार एवं विस्तार में मदद मिलेगी।

डेयरी सहकारी समिति में डिजिटलीकरण

अनुबंध-I

प्राथमिक डेरी सहकारी समितियों/मिल्क पूलिंग प्वाइंट्स (MPP) की स्थापना हेतु अगली 5 वर्षीय कार्य योजना

राज्य/केंद्र शासित प्रदेश	गांवों की कुल संख्या	मौजूदा गांवों में क्रियाशील सहकारी डीसीएस/एमपीपी कवरेज	नए डीसीएस/एमपीपी की स्थापना (लक्ष्य)					
			2024-25	2025-26	2026-27	2027-28	2028-29	Total
आंध्र प्रदेश	17,950	7,820	3,091	930	960	895	826	6,702
असम	27,959	551	135	160	200	280	325	1,100
बिहार	45,410	21,903	2,320	1,624	570	570	570	5,654
छत्तीसगढ	20,634	650	500	750	750	750	750	3,500
गोवा	429	174	2	3	3	4	4	16
गुजरात	19,040	20,173	238	245	240	228	222	1,173
हरियाणा	7,602	3,557	149	149	134	139	139	710
हिमाचल प्रदेश	21,254	567	90	70	55	45	40	300
जम्मू एवं कश्मीर	6,857	983	150	150	150	150	100	700
झारखंड	32,737	965	100	70	60	50	50	330
कर्नाटक	30,715	15,546	669	577	539	503	523	2,811
केरल	1,666	3,098	34	34	34	34	34	170
मध्य प्रदेश	55,891	8,193	512	532	597	597	597	2,835
महाराष्ट्र	44,532	12,559	133	161	196	206	182	878
मणिपुर	3,856	70	26	25	25	25	25	126
मेघालय	7,098	28	10	25	30	0	0	65
मिजोरम	875	22	15	15	15	10	10	65
नागालैंड	1,642	30	1	3	3	4	5	16
ओडिशा	52,245	3,425	1,209	714	823	2395	1306	6,447
पुदुचेरी	127	102	1	1	0	0	0	2
पंजाब	12,784	7,324	476	466	456	415	405	2,218
राजस्थान	46,903	16,489	1,300	1,340	1,365	1,400	1,437	6,842
सिक्किम	483	508	15	12	10	10	10	57
तमिलनाडु	18,696	10,119	227	236	248	259	271	1,241
तेलंगाना	11,226	4,008	372	187	182	84	80	905
त्रिपुरा	898	85	15	15	20	20	20	90
उत्तर प्रदेश	1,10,143	16,488	1,666	1,761	1,856	1,951	2,046	9,280
उत्तराखंड	17,325	2,550	222	193	193	188	166	962
पश्चिम बंगाल	41,006	1,570	295	301	310	241	244	1,391
कुल योग	**6,57,983**	**1,59,557**	**13,973**	**10,749**	**10,024**	**11,453**	**10,387**	**56,586**

अनुबंध-II

प्राथमिक डेरी सहकारी समितियों/मिल्क पूलिंग प्वाइंट्स (MPP) को सुदृढ़ करने हेतु अगली 5 वर्षीय कार्य योजना

राज्य/केंद्र शासित प्रदेश	मौजूदा गांवों में क्रियाशील सहकारी डीसीएस/एमपीपी कवरेज	डीसीएस/एमपीपी को सुदृढ़ करना (लक्ष्य)					
		2024-25	2025-26	2026-27	2027-28	2028-29	Total
आंध्र प्रदेश	7,820	211	632	527	421	316	2,107
असम	551	18	55	46	37	28	184
बिहार	21,903	610	1,830	1,525	1,220	915	6,100
छत्तीसगढ	650	45	135	113	90	68	451
गोवा	174	6	18	15	12	9	60
गुजरात	20,173	440	1,320	1,100	880	660	4,400
हरियाणा	3,557	119	356	297	237	178	1,187
हिमाचल प्रदेश	567	19	57	47	38	28	189
जम्मू एवं कश्मीर	983	33	98	82	66	49	328
झारखंड	965	32	96	80	64	48	320
कर्नाटक	15,546	410	1,230	1,025	820	615	4,100
केरल	3,098	83	250	208	167	125	833
मध्य प्रदेश	8,193	273	819	683	546	410	2,731
महाराष्ट्र	12,559	419	1256	1047	837	628	4,187
मणिपुर	70	2	7	6	5	4	24
मेघालय	28	1	3	2	2	1	9
मिजोरम	22	1	2	2	1	1	7
नागालैंड	30	1	3	3	2	2	11
ओडिशा	3,425	114	342	285	228	171	1,140
पुदुचेरी	102	3	10	9	7	5	34
पंजाब	7,324	244	732	610	488	366	2,440
राजस्थान	16,489	470	1,410	1,175	940	705	4,700
सिक्किम	508	17	51	42	34	25	169
तमिलनाडु	10,119	297	892	743	595	446	2,973
तेलंगाना	4,008	134	401	334	267	200	1,336
त्रिपुरा	85	3	9	7	6	4	29
उत्तर प्रदेश	16,488	500	1,499	1,250	1000	749	4,998
उत्तराखंड	2,550	85	255	213	170	128	851
पश्चिम बंगाल	1,570	52	157	131	105	79	524
कुल योग	**1,59,557**	**4,642**	**13,925**	**11,607**	**9,285**	**6,963**	**46,422**

अनुबंध-III

"डेरी गतिविधियों को आरंभ करने के लिए बहुउद्देशीय PACS (MPACS) को सहयोग प्रदान करने संबंधी योजना"

योजना के उद्देश्य

सदस्यों की समृद्धि के लिए अतिरिक्त आय सृजन गतिविधि के रूप में व्यवहार्य PACS /MPACS में डेरी की स्थापना करना।

योजना पात्रता मानदंड

PACS/MPACS के लिए पात्रता मानदंड

- उन सभी PACS/MPACS को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी, जो डेरी गतिविधियाँ शुरू करना चाहती हैं, बशर्ते कि वे निम्नलिखित मानदंडों को पूरा करें :
  - ग्राम पंचायत में डेरी गतिविधियों के लिए कोई प्राथमिक स्तर की दूध संकलन संस्था उपलब्ध नहीं है।
  - MPACS में डेरी परिचालन शुरू करने के लिए पर्याप्त दूध संकलन की संभावना है ।
  - MPACS डेरी सहकारी संस्था के परिचालन क्षेत्र के अंतर्गत आता है, ताकि दूध के लिए फारवर्ड लिंकेज सुनिश्चित किया जा सके।
- MPACS को वित्तपोषित करने का निर्णय पूरी तरह से NDDB के पास होगा, जो फिजीबिलिटी असेसमेंट और इस योजना में भाग लेने के लिए MPACS की इच्छा पर आधारित होगा।

योजना का स्वरूप

योजना के अंतर्गत प्रदान की जाने वाली सहायता

- दूध संकलन गतिविधियों की शुरूआत करने के लिए PACS/MPACS को प्रति PACS/MPACS अधिकतम् 40,000 रुपये की एकमुश्त वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। इस योजना के अंतर्गत वित्तपोषित किए जाने वाले प्रस्तावित मदों की अनंतिम सूची **अनुबंध-IV** में दी गई है।
- पायलट परियोजना के रूप में, यह योजना 1,000 चिह्नित PACS/MPACS में लागू की जाएगी।
- क्षेत्र में संचालित डेरी सहकारी संस्थाओं के माध्यम से PACS/MPACS को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
- क्षेत्र में संचालित डेरी सहकारी संस्थाओं के माध्यम से फारवर्ड लिंकेज उपलब्ध कराया जाएगा ।
- एनडीडीबी PACS/MPACS को तकनीकी सहायता प्रदान करेगी।

कार्यान्वयन की व्यवस्था

- इस योजना का कार्यान्वयन एनडीडीबी द्वारा किया जाएगा। एनडीडीबी द्वारा इस योजना का फिजिब्लिटी असेसमेंट, क्रियान्वयन, निगरानी और समीक्षा की जाएगी ।
- इस योजना के सुचारू कार्यान्वयन, फंड जारी करने और उसमें सहयोग प्रदान करने के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया है:
  - PACS/MPACS चिह्नित किए जाने के बाद, संबंधित PACS/MPACS की ओर से दूध संघ /महासंघ को एक शपथपत्र प्रस्तुत किया जाएगा, जिसमें दूध संकलन गतिविधियों की शुरूआत करने तथा इसकी निरंतरता सुनिश्चित करने में उनके द्वारा दी गई सहमति उल्लिखित हो।
  - इसके बाद, दूध संघ /महासंघ अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त करते हुए शपथपत्र (Undertaking) प्रस्तुत करेगा कि (i) PACS/MPACS में दूध संकलन शुरू करने के लिए हैंड होल्डिंग, तकनीकी, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण में सहायता प्रदान करेगा, (ii) निष्पक्ष और पारदर्शी दूध संकलन प्रणाली सुनिश्चित करेगा, (iii) PACS/MPACS से दूध संकलन करके और नियमित अंतराल पर भुगतान करते हुए फॉरवर्ड लिंकेज प्रदान करेगा और (iv) चिह्नित PACS/MPACS में सतत् दूध संकलन सुनिश्चित करने के साथ PACS/MPACS को आवश्यक सहायता प्रदान करेगा।
  - डेरी सहकारी संस्था उपर्युक्त सभी प्रतिबद्धताओं के साथ एनडीडीबी को अपना प्रस्ताव प्रस्तुत करेगी। प्रस्ताव प्राप्ति के बाद, एनडीडीबी स्वीकृति पत्र जारी करेगी और दूध संघ/महासंघ को अग्रिम राशि दी जाएगी।

योजना के अंतर्गत वित्तपोषित किए जाने वाले प्रस्तावित मदों की अनंतिम सूची

अनुबंध-IV

क्रम सं.	दूध संकलन उपकरणों/सहायक उपकरणों और दूध परीक्षण सहायक उपकरणों के नाम	अनुमानित संख्या (एक बार)
1	दूध संकलन ट्रे - 1.2 एमएम मोटाई एस एस 304 से निर्मित, साईज 440x590x65 एमएम, न्यूनतम वजन - 4200 ग्राम	1
2	दूध सैम्पलर- 1.2 एमएम मोटाई, एस एस 304 से निर्मित, न्यूनतम वजन-90 ग्राम	1
3	लैक्टोमीटर सिलेंडर - एस एस 304 पाइप से निर्मित, 1.6 एमएम मोटाई, न्यूनतम वजन 270 ग्राम	1
4	फनल विथ स्ट्रेनर - 1.2 एमएम मोटाई, एस एस 304 से निर्मित, न्यूनतम भार -1600 ग्राम	1
5	फनल फॉर स्ट्रेनर सीव, सामग्री एस एस 304 से निर्मित	1
6	माप 100 एमएल, 1.25 एमएम मोटाई, एस एस 304 से निर्मित, न्यूनतम वजन 125 ग्राम	1
7	माप 200 एमएल, 1.25 एमएम मोटाई, एस एस 304 से निर्मित, न्यूनतम वजन -180 ग्राम	1
8	माप 500 एमएल, 1.6 एमएम मोटाई, एस एस 304 से निर्मित, न्यूनतम वजन - 425 ग्राम	1
9	माप 1000 एमएल, 1.6 एमएम मोटाई, एस एस 304 से निर्मित, न्यूनतम वजन- 650 ग्राम	1
10	मिल्क कैन प्लंजर- एसएस 304 से निर्मित, न्यूनतम वजन-650 ग्राम	1
11	मिल्क बकेट - एस एस 200 से निर्मित, सीमलेस विथ बॉटम रिंग, 15 लीटर क्षमता, न्यूनतम वजन-1600 ग्राम	1
12	गेर्बर- 24 टेस्ट (मैनुअल/इलेक्ट्रिक)	1
13	लॉक स्टॉपर्स, पीतल (दर्जन)	2
14	लॉक स्टॉपर की (एल्यूमीनियम)	2
15	लैक्टोमीटर जील टाईप- 0 से 40, 1/2 भागयुक्त, कैलिब्रेशन - 84 F, शुद्धता + _0.25 LR	2
16	थर्मोमीटर (अल्कोहल), 0 से 1000 C, येलो बैक, शुद्धता 100%	2
17	पिपेट 10.75 एमएल, आईएसआई मार्क डबल टेस्टेड	2
18	ग्रेजुएटेड पिपेट 10 एमएल	2
19	टेस्ट ट्युब्स 18 X 150 एमएम	6
20	ब्यूटीरोमीटर (आईएसआई मेक), डबल टेस्टेड, दूध के लिए 0-10%, शुद्धता 100%	30
21	ग्लास ब्रेकर्स, 100 एमएल	1
22	ग्लास ब्रेकर्स, 500 एमएल	1
23	पोर्सेलेन डिश , 3 इंच	1
24	स्प्राइट लैंप, स्टेनलेस स्टील, 100 एमएल	1
25	ब्यूटीरोमीटर शैकिंग स्टैंड, 12 हॉल (HDPE)	2
26	प्लास्टिक सैपल बोटल्स, 50 एमएल, ढक्कन के साथ, खाद्य ग्रेड प्लास्टिक से निर्मित, न्यूनतम वजन -5.5 ग्राम	60
27	प्लास्टिक ट्रे फॉर होल्डिग-24 संख्या, खाद्य ग्रेड प्लास्टिक से निर्मित सुरक्षित सैपल बोटल्स, न्यूनतम वजन 300 ग्राम + _10 ग्राम	2
28	ट्रे फॉर रिएजेंट्स, साइज 16x12 इंच, खाद्य ग्रेड प्लास्टिक से निर्मित	1
29	प्लास्टिक टिल्ट माप 1 एमएल, रबर कॉर्क एवं अल्कोहल हेतु तथा प्लास्टिक बोतल- 250 एमएल	2
30	प्लास्टिक टिल्ट माप 10 एमएल रबर कॉर्क एवं एसिड हेतु तथा प्लास्टिक बोतल- 500 एमएल	2
31	टेस्ट ट्यूब स्टैंड 12 ट्युब्स की साइज 18X150 एमएम, एल्यूमीनियम	1
32	ब्यूटीरोमीटर की सफाई के लिए नायलॉन ब्रश, फुल लेंथ ब्रिसल्स	5
33	पिपेट की सफाई के लिए नायलॉन ब्रश, नायलॉन की लंबाई 4 इंच, कुल लंबाई 12 इंच	5
34	नायलॉन ब्रश 50 एमएल दूध के सैंपल बोतलों की सफाई के लिए, नायलॉन लंबाई 4 इंच, टेल और थिक स्टील वायर सहित	5
35	एसिड डायलुशन के लिए प्लास्टिक मापक जग, 1 लीटर	1
36	कैन खोलने के लिए प्लास्टिक का हथौड़ा	1
37	हीटर	1
40	ईडब्ल्यूएस-120 किलोग्राम या 200 किलोग्राम	1
41	मिल्क एनेलाइजर- 16000/- रुपये तक	1 Set
42	कैलकुलेटर	1
43	स्टेशनरी (क्रय रजिस्टर, भुगतान रजिस्टर, अनुदान, प्रस्ताव, पासबुक (40), डिमांड पैड रसीद बुक)	1 Set
45	मिल्क केन (4,600 रूपये प्रति एसएस कैन)	4

White Revolution 2.0

Preface

Hon'ble Prime Minister of India Shri Narendra Modi has observed that all efforts should be made to leverage the strengths of cooperatives and transform them into successful and vibrant business enterprises to realize the vision of "Sahakar-se-Samriddhi" as cooperatives hold the key to rural economic transformation in the country especially in agriculture and allied sectors with the promise of growth with equity. It is the policy of the Government to support the cooperative sector by ensuring convergence of the existing schemes and programmes of different Ministries and Departments. Under the able leadership and guidance of the first Cooperation Minister of the country Shri Amit Shah, the Ministry of Cooperation has taken the initiative to usher White Revolution 2.0.

White Revolution 2.0 is being launched with financial assistance to 1,000 Multipurpose Primary Agricultural Credit Cooperative Societies (MPACSs) at a rate of ₹ 40,000/- per MPACS for initiating dairy activities from the resources of National Dairy Development Board (NDDB). Subsequently this initiative is to be driven by the financial assistance under the proposed National Programme for Dairy Development 2.0 (NPDD 2.0) of Department of Animal Husbandry & Dairying, Government of India. The "Cooperative Movement" will be further strengthened from this initative.

The cooperative led "White Revolution 2.0" is aimed at expanding cooperative coverage, employment generation, and women's empowerment with an objective "To increase the milk procurement of dairy cooperatives by 50% from the present level over the next five years by providing market access to dairy farmers in uncovered areas and increasing the share of dairy cooperatives in organised sector."

Project strategy

To achieve the objective envisaged under White Revolution 2.0, cooperative milk procurement is required to increase by about 9 per cent per annum as against the present annual growth of 6 per cent.

- Setting up of viable dairy cooperatives in each uncovered Panchayat/village and strengthening the existing PACS/dairy cooperative societies.
- Initiative to be implemented by leveraging the 'whole-of-Government' approach with the support of National Dairy Development Board (NDDB) through convergence of various schemes of animal husbandry & dairying.

In absolute terms, by the end of fifth year, the milk procurement by dairy cooperatives is expected to reach 1000 Lakh Kg Per Day. This will be achieved through two pronged strategies viz.

(i) expanding the coverage of dairy cooperatives
(ii) deepening the reach of dairy cooperatives

The year-wise proposed targets under White Revolution 2.0 are as under

Key Parameters	Base year 2023-24	2024-25	2025-26	2026-27	2027-28	2028-29
Cooperative milk procurement (LKgPD)	660	720	780	847	923	1,007

Cheese Plant, Sabar Dairy, Sabarkantha, Gujarat

Aavin Dairy Plant, Sivakasi, Tamil Nadu

Automatic Milk Collection Unit (AMCU)

Plan to establish/strengthen one lakh dairy cooperative societies (DCS) for achieving the objectives of White Revolution 2.0

To achieve this, an action plan has been prepared by NDDB for establishing about 56,000 new Multipurpose DCS (MDCS) during the next five years. Wherever feasible, instead of creating new village level institution (MDCS/ MPACS), efforts will be made to leverage existing PACS in uncovered areas by initiating milk procurement activities in PACS.

Further, it is envisaged that about 46,000 existing village level DCS/ PACS will be strengthened in terms of better and advanced milk procurement and testing infrastructure e.g. Automatic Milk Collection Unit (AMCU), Data Processor Milk Collection Unit (DPMCU), testing equipment, Bulk Milk Coolers, etc. as per the requirement and they will function as MDCS/ MPACS.

State-wise details of new/ to be strengthened DCSs are given at **ANNEXURE-I** and **ANNEXURE-II** respectively.

Proposed National Programme for Dairy Development 2.0 (NPDD 2.0)

The targets of White Revolution 2.0 have been subsumed under the newly proposed Central Sector Scheme namely, National Programme for Dairy Development (NPDD) 2.0 of Department of Animal Husbandry and Dairying, MOFAH&D.

Under the scheme, financial assistance for following components has been envisaged:

a. Setting up of village level milk procurement system

b. Milk Chilling facilities for quality milk procurement

c. Training and capacity building

The EFC note of the proposed NPDD 2.0 has been circulated and is likely to be approved soon. The NPDD 2.0 will be implemented as per guidelines issued by DAHD.

Outcome of the project :

- It will provide market access to smallholder dairy farmers while ensuring fair and remunerative prices.
- It will help in furthering the network of primary dairy cooperatives and help strengthening the entire milk value chain including milk procurement, testing, chilling, logistics and processing infrastructure.
- Women being an important stakeholder in dairy, greater emphasis on having women as members.
- Enhanced procurement would help in increasing the share of organised sector in dairy industry which is still dominated by the unorganised sector. This will help in ensuring food safety & quality control and increased availability of fresh and hygienic milk & milk products.
- The initiatives will help in developing the sector and increasing milk production to meet the domestic demand and also tap the export potential.

Banas Dairy Plant, Banaskantha, Gujarat

Gokul Dairy Plant, Kolhapur, Maharashtra

Varanasi Dairy Plant, Varanasi, Uttar Pradesh

Nandini Dairy Plant, Channarayapatna, Karnataka

NDDB pilot projects to establish DCS in uncovered gram panchayats

To understand the nature and magnitude of support required, NDDB has rolled out a pilot in February 2023 for setting up DCSs in identified pockets of uncovered panchayats of Jind (Haryana), Indore (Madhya Pradesh), and Chikmagalur (Karnataka) district. Under the pilot, 79 DCSs have been established which are collectively procuring 15 TLPD Milk from about 2500 farmers. Total outlay of the project is ₹3.8 Crore.

NDDB Scheme to support MPACS to initiate milk procurement activities

In consonance with the White Revolution 2.0, to initiate milk procurement activities as an additional income generating activity in PACS/ MPACS, NDDB has decided to provide financial and technical support to PACS/ MPACS through its scheme. Under the scheme, 1000 MPACS will be provided a grant of ₹40,000 per PACS/ MPACS for procuring basic milk procurement and testing equipment. The scheme will be implemented through Dairy Cooperative Institutions across the country. Total outlay of the scheme will be ₹4.00 Crore, which will be financed through NDDB's fund. The scheme will cover 1000 PACS/ MPACS and NDDB has started receiving expression of interests from various states for availing benefit under the scheme. The targets achieved in this scheme will be subsumed in the White Revolution 2.0.

The details of the scheme along with guidelines of the scheme are provided at **ANNEXURE-III**.

Since the aforesaid scheme is a part of White Revolution 2.0, the launch of this scheme will provide wider publicity and circulation among the stakeholders and will help increase the reach and coverage of the scheme.

Digitalisation at dairy cooperative society

ANNEXURE-I

Action Plan for setting up of primary dairy cooperative societies/Milk Pooling Points (MPPs) for next 5 years

State/ UT	Total No. of Villages	Existing Coop Functional DCS/ MPP existing villages coverage	New DCS/ MPP to be established (Target)					
			2024-25	2025-26	2026-27	2027-28	2028-29	Total
Andhra Pradesh	17,950	7,820	3,091	930	960	895	826	6,702
Assam	27,959	551	135	160	200	280	325	1,100
Bihar	45,410	21,903	2,320	1,624	570	570	570	5,654
Chhattisgarh	20,634	650	500	750	750	750	750	3,500
Goa	429	174	2	3	3	4	4	16
Gujarat	19,040	20,173	238	245	240	228	222	1,173
Haryana	7,602	3,557	149	149	134	139	139	710
Himachal Pradesh	21,254	567	90	70	55	45	40	300
Jammu & Kashmir	6,857	983	150	150	150	150	100	700
Jharkhand	32,737	965	100	70	60	50	50	330
Karnataka	30,715	15,546	669	577	539	503	523	2,811
Kerala	1,666	3,098	34	34	34	34	34	170
Madhya Pradesh	55,891	8,193	512	532	597	597	597	2,835
Maharashtra	44,532	12,559	133	161	196	206	182	878
Manipur	3,856	70	26	25	25	25	25	126
Meghalaya	7,098	28	10	25	30	0	0	65
Mizoram	875	22	15	15	15	10	10	65
Nagaland	1,642	30	1	3	3	4	5	16
Odisha	52,245	3,425	1,209	714	823	2395	1306	6,447
Puducherry	127	102	1	1	0	0	0	2
Punjab	12,784	7,324	476	466	456	415	405	2,218
Rajasthan	46,903	16,489	1,300	1,340	1,365	1,400	1,437	6,842
Sikkim	483	508	15	12	10	10	10	57
Tamil nadu	18,696	10,119	227	236	248	259	271	1,241
Telangana	11,226	4,008	372	187	182	84	80	905
Tripura	898	85	15	15	20	20	20	90
Uttar Pradesh	1,10,143	16,488	1,666	1,761	1,856	1,951	2,046	9,280
Uttarakhand	17,325	2,550	222	193	193	188	166	962
West Bengal	41,006	1,570	295	301	310	241	244	1,391
Grand Total	**6,57,983**	**1,59,557**	**13,973**	**10,749**	**10,024**	**11,453**	**10,387**	**56,586**

ANNEXURE-II

Action Plan for strengthening of primary dairy cooperative societies/Milk Pooling Points (MPPs) for next 5 years

State/ UT	Existing Coop Functional DCS/ MPP existing villages coverage	DCS/ MPP to be Strengthened (Target)					
		2024-25	2025-26	2026-27	2027-28	2028-29	Total
Andhra Pradesh	7,820	211	632	527	421	316	2,107
Assam	551	18	55	46	37	28	184
Bihar	21,903	610	1,830	1,525	1,220	915	6,100
Chhattisgarh	650	45	135	113	90	68	451
Goa	174	6	18	15	12	9	60
Gujarat	20,173	440	1,320	1,100	880	660	4,400
Haryana	3,557	119	356	297	237	178	1,187
Himachal Pradesh	567	19	57	47	38	28	189
Jammu & Kashmir	983	33	98	82	66	49	328
Jharkhand	965	32	96	80	64	48	320
Karnataka	15,546	410	1,230	1,025	820	615	4,100
Kerala	3,098	83	250	208	167	125	833
Madhya Pradesh	8,193	273	819	683	546	410	2,731
Maharashtra	12,559	419	1256	1047	837	628	4,187
Manipur	70	2	7	6	5	4	24
Meghalaya	28	1	3	2	2	1	9
Mizoram	22	1	2	2	1	1	7
Nagaland	30	1	3	3	2	2	11
Odisha	3,425	114	342	285	228	171	1,140
Puducherry	102	3	10	9	7	5	34
Punjab	7,324	244	732	610	488	366	2,440
Rajasthan	16,489	470	1,410	1,175	940	705	4,700
Sikkim	508	17	51	42	34	25	169
Tamil Nadu	10,119	297	892	743	595	446	2,973
Telangana	4,008	134	401	334	267	200	1,336
Tripura	85	3	9	7	6	4	29
Uttar Pradesh	16,488	500	1,499	1,250	1000	749	4,998
Uttarakhand	2,550	85	255	213	170	128	851
West Bengal	1,570	52	157	131	105	79	524
Grand Total	**1,59,557**	**4,642**	**13,925**	**11,607**	**9,285**	**6,963**	**46,422**

ANNEXURE-III

Scheme on "Supporting Multipurpose PACS (MPACS) to initiate viable dairy activities"

Scheme Objective

To establish dairy in viable PACS/MPACS as an additional income generating activity for betterment of members.

Scheme Eligibility Criteria

Eligibility Criteria for PACS/ MPACS

- The financial assistance would be provided to all PACS/ MPACS that wish to initiate dairy activities, subject to fulfilment of the following criteria:
  - The Gram Panchayat does not have any primary level milk collection institution for dairy activities.
  - The MPACS has adequate milk potential to initiate viable dairy operations.
  - The MPACS is under the operational area of a Dairy Cooperative Institution so that the forward linkages for onward transportation of milk can be ensured.
- The decision to fund the MPACS shall entirely lie with NDDB based on feasibility assessment and willingness of MPACS to participate in the scheme.

Scheme Design

Assistance to be provided under the scheme

- One-time financial support up to a maximum of ₹40,000 per PACS/ MPACS will be provided to viable PACS/ MPACS to initiate milk procurement activities. The tentative list of items proposed to be funded under the scheme is furnished at **ANNEXURE-IV**.
- As a pilot project, the scheme will be rolled out in 1,000 identified PACS/ MPACS.
- The financial assistance to PACS/ MPACS will be routed through Dairy Cooperative Institution operating in the region.
- Forward linkages will be provided through Dairy Cooperative Institution operating in the region.
- NDDB will provide technical support to the PACS/ MPACS.

Implementation Arrangement

- The scheme will be implemented by NDDB, wherein NDDB shall be responsible for feasibility assessment, implementation, monitoring and review of the scheme.
- For implementation of the scheme, the following process has been put in place for facilitation and release of funds under the scheme:
  - Upon identification of PACS/ MPACS, an undertaking from the concerned PACS/ MPACS shall be submitted to Milk Union/ Federation indicating its willingness to start milk procurement activities and ensuring its sustainability.
  - Subsequently, Milk Union/ Federation shall submit the undertaking indicating its commitment (i) to provide initial handholding, technical, training and capacity building support for initiating milk procurement at PACS/ MPACS, (ii) to ensure fair and transparent milk procurement mechanism, (iii) to provide forward linkages by collecting milk from the PACS/ MPACS and making payments at a regular interval, and (iv) to ensure sustainable milk procurement operations in the identified PACS/ MPACS and provide all necessary support to PACS/ MPACS.
  - The Dairy Cooperative Institution will submit a proposal to NDDB along with all above undertakings. Subsequent to receipt of the proposal, NDDB shall issue sanction letter and advance to the Milk Union/ Federation.

Tentative list of items proposed to be funded under the scheme

ANNEXURE-IV

Sr. No.	Name of Milk Collection Equipments/ Accessories and Milk Testing accessories	Indicative Quantity one time (nos.)
1	Milk Collection Tray, made 1.2mm thick S S 304, size 440x 590x65 mm, Minimum weight -4200gm.	1
2	Milk Sampler, Made from 1.2mm thick S S 304. Minimum weight -90gm	1
3	Lactometer Cylinder, made from S S 304 Pipe having 1.6mm wall thickness, Minimum weight 270 gm	1
4	Funnel with Strainer, made from 1.2mm thick S S 304. Minimum weight -1600gm	1
5	Strainer Sieve for Funnel, Material S S 304	1
6	Measure 100 ML, Made from 1.25mm thick S S 304. Minimum weight 125gm	1
7	Measure 200 ML, made from 1.25mm thick S S 304. Minimum weight -180gm	1
8	Measure 500ML, made from 1.6mm thick S S 304. Minimum weight - 425gm	1
9	Measure 1000ML, made form 1.6mm thick S S 304. Minimum weight- 650gm	1
10	Milk Can Plunger, made from SS 304. Minimum weight-650gm	1
11	Milk Bucket, made from S S 200 series, seamless with bottom ring, 15 litre capacity. Minimum weight -1600 gm	1
12	Gerber 24 tests (Manual/Electric)	1
13	Lock Stoppers, Brass (Dozen)	2
14	Lock Stopper Keys (Aluminium)	2
15	Lactometer Zeal type ,0 to 40 with ½ division, Calibrated at 84 F, Accuracy+_0.25 LR	2
16	Thermometer (Alcohol), 0 to 1000 C, yellow back, accuracy 100%	2
17	Pipette 10.75 ml, ISI mark Double tested	2
18	Graduated pipettes 10 ml	2
19	Test tubes 18 X 150 mm	6
20	Butyrometers (ISI Make), double tested, for milk 0-10%, accuracy 100%	30
21	Glass Beakers, 100 ml	1
22	Glass Beakers, 500 ml	1
23	Porcelain dish, 3 Inch	1
24	Sprit lamp, Stainless Steel, 100 ml.	1
25	Butyrometers shaking stand, 12 holes (HDPE)	2
26	Plastic sample bottles, 50 ml, with cap, made from food grade plastic, Minimum weight-5.5 gm	60
27	Plastic tray for holding 24 Nos. sample bottles securely, made from food grade plastic, minimum weight 300 gm +_10 gm	2
28	Tray for reagents, Size 16x12 Inches, made from food grade plastic	1
29	Plastic tilt measure 1ml for alcohol with rubber cork & with plastic bottle of 250 ml.	2
30	Plastic tilt measure 10 ml for acid with rubber cork & with plastic bottle of 500 ml	2
31	Test Tube Stand for 12 tubes of size18X150 mm, Aluminium	1
32	Nylon Brush for cleaning Butyrometers, full length bristles	5
33	Nylon Brush for cleaning pipettes, nylon length 4 Inches, total length 12 Inches	5
34	Nylon Brush for cleaning 50 ml milk sample bottles, nylon length 4", with tail & thick steel wire	5
35	Plastic measuring jug for acid dilution ,1 Litre	1
36	Plastic hammer for can opening	1
37	Heater	1
40	EWS – 120 Kg or 200 Kg	1
41	Milk Analyser – up to ₹16000/-	1 Set
42	Calculator	1
43	Stationery (purchase reg, bhugtan register, Anudan, Prastav, passbook (40), demand pad rasid book)	1 Set
45	Milk Can (@ ₹4,600 per SS Can)	4

सत्यमेव जयते

Department of Animal Husbandry and Dairying
Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying
Government of India

Ministry of Cooperation | सहकारिता मंत्रालय
Government of India | भारत सरकार

NATIONAL DAIRY DEVELOPMENT BOARD

श्वेत क्रांति 2.0

White Revolution 2.0